06/05/2024

शामिल विषय (TOPICS COVERED)

1. तालवाद्य वादक अरविंदाक्षन मरार का निधन (6 मई) (स्टेट पीसीएस)
2. प्रधानमंत्री के भाषण आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में हैं (6 मई) (GS PAPER II: चुनाव)
3. भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय (6 मई) (GS PAPER III: आंतरिक सुरक्षा)

सूडान के गृह युद्ध का अवलोकन (6 मई)

- सूडान में गृह युद्ध केवल दो जनरलों के बीच सत्ता संघर्ष नहीं है, बल्कि 1956 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से देश की शासकीय संरचना के भीतर एक लंबे समय से चले आ रहे संकट को दर्शाता है।
- स्वतंत्रता के बाद से सूडान में 35 तख्तापलट और तख्तापलट के प्रयास हुए हैं, जो किसी भी अफ्रीकी देश में सबसे अधिक है।
- विभिन्न विद्रोह भड़क उठे हैं, जिनमें दक्षिण में 56 वर्ष पुराना विद्रोह भी शामिल है, जिसके कारण 2011 में दक्षिण सूडान का निर्माण हुआ तथा 2003 में डारफुरियन विद्रोह भी शामिल है, जो क्षेत्र की गैर-अरब आबादी के प्रति केंद्र सरकार द्वारा कथित भेदभाव के कारण हुआ था।
- सूडान गहरे पहचान संकट से ग्रस्त है, जो विविधता को प्रबंधित करने और साझा दृष्टिकोण को स्पष्ट करने में उत्तरोत्तर सरकारों की विफलता के कारण और भी अधिक गंभीर हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप धन और संसाधनों का अनुचित वितरण हो रहा है।
- सूडान की 49 मिलियन की आबादी में 19 प्रमुख जातीय समूह और लगभग 597 जातीय उप-समूह शामिल हैं, जो अनेक भाषाएँ और बोलियाँ बोलते हैं।
- सूडानी अरब सबसे बड़ा जातीय समूह है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 70% है, तथा राजनीतिक और आर्थिक शक्ति खार्तूम में केंद्रित है।
- सूडान में शांति प्राप्त करने के लिए डारफुर, दक्षिण कोर्डोफन और नुबा पर्वत जैसे संघर्ष क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाली आबादी की चिंताओं को संबोधित करने की आवश्यकता है, साथ ही सशस्त्र हिंसा के मूल कारणों जैसे हाशिए पर जाने, धर्म-राज्य संबंध, शासन, संसाधन साझाकरण, भूमि मुद्दों से निपटने की भी आवश्यकता है। सामाजिक न्याय, और राष्ट्रीय समानता।

आज़ादी के प्रारंभिक वर्ष

- 1956 में स्थापित सूडानी सरकार ने विविध समुदायों को अलग-थलग करते हुए महदीवाद सिद्धांतों पर आधारित अरब और इस्लामी पहचान पर जोर दिया।
- 1989 में, उमर अल-बशीर के नेतृत्व में और मुस्लिम ब्रदरहुड द्वारा समर्थित नेशनल इस्लामिक फ्रंट ने इस्लामिक राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया।

Patriot IAS

- शासन ने एक आंतरिक सुरक्षा तंत्र को नियोजित किया, असंतुष्टों को गिरफ्तार किया, और नए दंड संहिता और "पीपुल्स पुलिस" के निर्माण के माध्यम से इस्लामीकरण के एजेंडे को लागू किया।
- अल-बशीर ने 2003 में दारफुर विद्रोह को दबाने के लिए जंजावीद मिलिशिया को शामिल किया, जिससे शासन को सेना के अभिजात वर्ग को संघर्ष क्षेत्रों से दूर रखने की अनुमति मिली।
- 2013 में, अल-बशीर ने जंजावीद को रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) के रूप में औपचारिक रूप दिया, और उन्हें अपनी सीधी कमान के तहत सेना में एकीकृत किया।
- मोहम्मद हमदान डागालो (हेमेदती) को शक्ति और प्रभाव को मजबूत करने के लिए आरएसएफ का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था।
- 2018 में गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसके कारण अप्रैल 2019 में सेना द्वारा अल-बशीर को हटा दिया गया और आपातकाल की स्थिति की घोषणा की गई।
- एक संक्रमणकालीन सैन्य सरकार के बावजूद, चल रहे विरोध प्रदर्शनों में नागरिक नेतृत्व की मांग की गई, जिसके परिणामस्वरूप अगस्त 2019 में अफ्रीकी संघ की मध्यस्थता में एक शक्ति-साझाकरण समझौता हुआ।
- चुनौतियाँ बनी रहीं, जिनमें सितंबर 2021 में एक असफल तख्तापलट का प्रयास और अक्टूबर 2021 में जनरल अब्देल फत्ताह अल-बुरहान के नेतृत्व में एक और तख्तापलट शामिल है, जिसने लोकतांत्रिक परिवर्तन को बाधित किया।
- अप्रैल 2023 के युद्ध से पहले नागरिक विरोध प्रदर्शनों को हिंसक रूप से दबा दिया गया, जिससे सेना और आरएसएफ नेताओं के बीच तनाव बढ़ गया।

मिलिशिया-प्रभुत्व वाला राज्य बनाना

- रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) सूडानी सशस्त्र बलों के प्रतिसंतुलन के रूप में उभरी।
- उन्होंने रणनीतिक रूप से हजारों लड़ाकों को प्रमुख शहरों, सीमावर्ती क्षेत्रों और सोने की खदानों जैसे आर्थिक केंद्रों पर तैनात किया।
- रूस ने सूडानी सोने तक पहुंच प्राप्त करने के लिए वैगनर समूह के माध्यम से आरएसएफ के साथ संबंध स्थापित किये।
- तीन स्थितियों ने योगदान दिया

खुलासा

- हेमेदती का संप्रभुता परिषद के उपाध्यक्ष पद पर पहुंचना सूडान के लोकतांत्रिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण था।
- रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) को भंग करने या हेमेदती को किनारे करने से आरएसएफ के आकार और व्यावसायिक हितों के कारण अशांति फैलने का खतरा पैदा हो गया।
- राज्य पर मिलिशिया का प्रभुत्व सेना की प्रतिक्रिया में देरी कर सकता है, जिससे संभावित रूप से संघर्ष बढ़ सकता है।
- प्रारंभ में, हेमेदती ने बलपूर्वक सत्ता पर कब्ज़ा करने से परहेज किया और अपने सैनिकों को सेना के सहयोगियों के रूप में शामिल किया, जिसमें महत्वपूर्ण आर्थिक उद्यम भी थे।
- अक्टूबर 2021 के सैन्य तख्तापलट ने सूडान की लोकतांत्रिक प्रगति को रोक दिया, जिससे दमन और आर्थिक गिरावट आई।
- इसके बीच, आरएसएफ ने व्यावसायिक उद्यमों और संलग्नताओं के माध्यम से अपने प्रभाव का विस्तार किया।

PatrioticIAS

- आर.एस.एफ. को एकीकृत करने का सेना का प्रयास विफल हो गया, जिसके परिणामस्वरूप सशस्त्र टकराव हुआ और आर.एस.एफ. ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्ज़ा कर लिया।

आगे क्या

- सूडान को पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है।
- इसके लिए एक पारदर्शी, नागरिक नेतृत्व वाली सरकार की आवश्यकता है जो सूडानी लोगों का प्रतिनिधित्व करती हो।
- सरकार को निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों की आवाज सुनने को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- सूडान के उत्तर-औपनिवेशिक राज्य के पुनर्निर्माण के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, ताकि सभी नागरिकों के अधिकारों का समावेश और संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

तीसरे चरण के चुनाव के लिए 94 लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार समाप्त (6 मई) (GS PAPER II: चुनाव)

- काल **शाम 6 बजे शुरू हुआ** रविवार को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा।
- कुल निर्वाचन क्षेत्रों में से आधे से अधिक के लिए मतदान 7 मई को इस चरण के दौरान होगा।
- इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, प्रहलाद जोशी और ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले शामिल हैं।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 मौन अवधि के दौरान चुनाव प्रचार गतिविधियों पर रोक लगाती है।
- अभियान गतिविधियों में सार्वजनिक बैठकें, जुलूस, तथा टेलीविजन या इसी तरह के मंचों पर चुनावी सामग्री प्रदर्शित करना शामिल है।
- मौन अवधि के दौरान, मौन अवधि वाले निर्वाचन क्षेत्रों में किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संदर्भ की अनुमति नहीं है।
- स्टार प्रचारकों और राजनीतिक नेताओं को चुनावी मामलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया को संबोधित करने या साक्षात्कार देने पर प्रतिबंध है।
- तीसरे चरण के 94 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया 12 अप्रैल को शुरू हुई और 19 अप्रैल को समाप्त हुई।
- इस चरण में गुजरात की 25, गोवा की 2 और कर्नाटक की 14 सीटें शामिल हैं।
- बसपा उम्मीदवार की मृत्यु के कारण बैतूल सीट पर चुनाव दूसरे चरण से तीसरे चरण में स्थानांतरित कर दिया गया।
- इस चरण में मतदान करने वाले अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं।
- जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग-राजौरी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान छठे चरण में 25 मई को होगा।

PatriotIAS

सभी रेलगाड़ियों में दिव्यांग व्यक्तियों को रियायतों के बावजूद आरक्षण मिलेगा (6 मई) (GS PAPER II: समाज का कमजोर वर्ग)

- मंत्रालय ने सभी रेलगाड़ियों में विकलांग व्यक्तियों के लिए कोटा स्वीकृत कर दिया है, भले ही रियायती किराया सुविधा उपलब्ध हो या न हो।
- कोटे में स्लीपर क्लास में चार बर्थ, थ्री-टियर एसी में चार बर्थ और गरीब रथ ट्रेनों के विशेष रूप से डिजाइन किए गए द्वितीय श्रेणी लगेज-सह-गार्ड कोच में चार बर्थ शामिल होंगे ।
- इसके अतिरिक्त, इन श्रेणियों के दो से अधिक कोचों वाली ट्रेनों में आरक्षित द्वितीय श्रेणी सिटिंग और एसी चेयर कार में चार सीटें और वंदे भारत ट्रेनों में चार सीटें आवंटित की जाएंगी ।
- विशेष रूप से डिज़ाइन की गई सीटें, जैसे सीट नं. 40, आठ-कार और 16-कार ट्रेनों के कुछ डिब्बों में विकलांग यात्रियों के लिए उपलब्ध होगा, साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में एस्कॉर्ट या अटेंडर के लिए एक अतिरिक्त सीट भी उपलब्ध होगी।
- दुरुपयोग को रोकने के लिए , विकलांगता कोटा के तहत ऑनलाइन बुकिंग रेलवे द्वारा जारी विशिष्ट पहचान पत्र वाले लोगों तक ही सीमित रहेगी । काउंटर बुकिंग के लिए, कार्ड या रियायती प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- रेलवे की आईटी शाखा, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, रियायती किराया सुविधाओं के बिना ट्रेनों में भी इन कार्डों को सत्यापित करने के लिए आरक्षण सॉफ्टवेयर को संशोधित करेगी।
- यदि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में विकलांग लोगों के लिए विशेष रूप से निर्दिष्ट सीटें बुक की गई हैं, लेकिन उनके साथ आने वाले एस्कॉर्ट के लिए सीटें खाली रहती हैं, तो वे खाली सीटें विकलांग यात्रियों को आवंटित की जाएंगी।
- पहले, विकलांग लोगों और उनके अनुरक्षकों के लिए आवास केवल किराए में छूट के साथ बुकिंग की अनुमति देने वाली ट्रेनों में प्रदान किया जाता था।
- वरिष्ठ नागरिकों और अन्य श्रेणियों के यात्रियों के लिए रेल यात्रा रियायतें बहाल करने पर कोई निर्णय नहीं किया गया है, जिन्हें महामारी से पहले रियायती किराया मिलता था।

तालवाद्य वादक अरविंदाक्षन मरार का निधन (6 मई) (स्टेट पीसीएस)

Patriot IAS

- **मेम्ब्रानोफोन्स:** इन उपकरणों में एक फैली हुई झिल्ली या ड्रमहेड होता है, जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करता है। मेम्ब्रानोफोन के उदाहरणों में ड्रम, टिमपनी, बोंगो और डीजेम्बेस शामिल हैं।

Ofanda, Jezreel
10-Tranquility

Idiophone - an instrument the whole of which vibrates to produce a sound when struck, shaken, or scraped, such as a bell, gong, or rattle.

Examples of idiophones

- **Xylophone** is a musical instrument in the percussion family that consists of wooden bars struck by mallets.

- **Rattle** a type of percussion instrument which produces a sound when shaken. Rattles are described in the Hornbostel–Sachs system as Shaken Idiophones

- **Jew's harp** is a lamellophone instrument, which is in the category of plucked idiophones.

- **Wood block** is a small slit drum made from a single piece of wood and used as a percussion instrument.

- **Bell** is a directly struck idiophone percussion instrument. Most bells have the shape of a hollow cup that when struck vibrates in a single strong strike tone, with its sides forming an efficient resonator.

Membranophone- is any musical instrument which produces sound primarily by way of a vibrating stretched membrane. It is one of the four main divisions of instruments in the original Hornbostel-Sachs scheme of musical instrument classification.

Examples of Membranophone

- **Djembe** is a rope-tuned skin-covered goblet drum played with bare hands, originally from West Africa.

- **इडियोफोन:** ये उपकरण तब ध्वनि उत्पन्न करते हैं जब उनका पूरा शरीर कंपन करता है। इडियोफोन के उदाहरणों में झांझ, घंटियाँ, घड़ियाल, लकड़ी के ब्लॉक और त्रिकोण शामिल हैं।
  ताल वाद्ययंत्रों को विभिन्न तरीकों से बजाया जा सकता है, जिसमें लाठी, हथौड़े, हाथ या यहां तक कि पैरों से भी शामिल है। इनका उपयोग शास्त्रीय और जैज़ से लेकर रॉक और पॉप तक संगीत शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जाता है।
  यहां ताल वाद्य यंत्रों के बारे में कुछ अन्य रोचक तथ्य दिए गए हैं:
- शब्द "पर्क्यूशन" लैटिन शब्द " परक्यूटेरे " से आया है, जिसका अर्थ है "हमला करना।"
- सबसे पुराने ज्ञात ताल वाद्य यंत्र ड्रम हैं, जो लगभग 6,000 ईसा पूर्व के पुरातात्विक स्थलों में पाए गए हैं।
- ताल वाद्ययंत्र कई संस्कृतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और अक्सर धार्मिक समारोहों और अनुष्ठानों में उपयोग किए जाते हैं।
- सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के तालवाद्य खंड में आम तौर पर टिम्पनी, स्नेयर ड्रम, बेस ड्रम, झांझ और त्रिकोण शामिल होते हैं।
- तालवादक एक संगीतकार होता है जो तालवाद्य यंत्र बजाता है।
- केलाथ प्रख्यात तालवादक अरविंदाक्षन मरार का 82 वर्ष की आयु में त्रिशूर में निधन हो गया।
- वह साढ़े चार दशकों से अधिक समय तक त्रिशूर पूरम के तालवाद्य समूहों में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते थे।
- इलांजिथारा में उनकी भागीदारी के लिए जाना जाता था त्रिशूर पूरम उत्सव का मेलम और अन्य प्रसिद्ध पूरम।

- **परमेक्कावु** की पर्कशन टीम के हिस्से के रूप में काम किया **देवास्वोम** 13 साल तक.
- बाद में, वह **तिरुवंबदी में शामिल हो गए देवास्वोम** परमेक्कावु लौटने से पहले नौ साल तक , जहां उन्होंने 23 साल तक काम किया।
- **त्रिशूर पूरम** के जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य में एक अभिन्न उपस्थिति बना दिया और केरल में अन्य त्यौहार।

टाइप 214 पनडुब्बी की बुनियादी विशिष्टताएँ:

- लंबाई: 65 मीटर (213 फीट)
- बीम: 6.3 मीटर (20 फीट 8 इंच)
- ड्राफ्ट: 6 मीटर (19 फीट 8 इंच)
- सतही विस्थापन: 1,400 टन (1,540 लघु टन)
- जलमग्न विस्थापन: 1,850 टन (2,040 लघु टन)
- सीमेंस पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट झिल्ली (पीईएम) हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं का उपयोग करके वायु-स्वतंत्र प्रणोदन (एआईपी) प्रणाली के साथ डीजल-इलेक्ट्रिक प्रणोदन
- आयुध: 8 × 533 मिमी (21.0 इंच) टारपीडो ट्यूब; 12 टॉरपीडो या सब-हार्पून मिसाइलों तक
- पूरक: 27 (5 अधिकारी + 22 दल)
- सहनशक्ति: 21 दिन (अकेले बैटरी पर), 84 दिन (एआईपी के साथ)

टाइप 214 पनडुब्बी एक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है जिसमें वायु-स्वतंत्र प्रणोदन (एआईपी) प्रणाली है। एआईपी प्रणाली पनडुब्बी को अपनी बैटरियों को रिचार्ज करने के लिए सतह पर आए बिना लंबे समय तक पानी के नीचे रहने की अनुमति देती है। यह टाइप 214 पनडुब्बी को बहुत ही गुप्त और प्रभावी पनडुब्बी बनाता है।

टाइप 214 पनडुब्बी का संचालन करने वाली नौसेनाओं में हेलेनिक नौसेना (ग्रीस), कोरिया गणराज्य नौसेना (दक्षिण कोरिया), पुर्तगाली नौसेना और तुर्की नौसेना शामिल हैं।

- **थिसेनक्रुप एजी** एक जर्मन कंपनी है जो औद्योगिक इंजीनियरिंग और इस्पात उत्पादन में विशेषज्ञता रखती है।
- इसका गठन 1999 में थिसेन एजी और क्रुप के विलय से हुआ था।
- कंपनी का परिचालन मुख्यालय जर्मनी के डुइसबर्ग और एसेन में स्थित है।
- थिसेनक्रुप का दावा है कि वह विश्व की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनियों में से एक है तथा 2015 में राजस्व के आधार पर इसे विश्व में दसवीं सबसे बड़ी कंपनी माना गया था।
- यह **दुनिया भर में 670 सहायक कंपनियों के माध्यम से काम करता है** ।
- थिसेनक्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक अल्फ्रेड क्रुप वॉन बोहलेन अंड हालबाक फाउंडेशन और सेवियन कैपिटल हैं।
- थिसेनक्रुप के उत्पाद पोर्टफोलियो में मशीनें, औद्योगिक सेवाएं, हाई-स्पीड रेलगाड़ियां, लिफ्ट और जहाज निर्माण शामिल हैं।
- इसकी सहायक कंपनी, थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स, जर्मन और विदेशी नौसेनाओं के लिए फ्रिगेट, कॉर्वेट और पनडुब्बियां बनाती है।
- 2018 में, थिसेनक्रुप ने दो कंपनियों, थिसेनक्रुप इंडस्ट्रियल्स और थिसेनक्रुप मैटेरियल्स में विभाजित होने की योजना की घोषणा की, लेकिन बाद में मई 2019 में इस योजना को रद्द कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी अधिकारी की जमानत खारिज की (6 मई) (GS PAPER II: राज्य और नागरिक के बीच संबंध)

- सर्वोच्च न्यायालय ने 13 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोपी पुलिस अधिकारी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को खारिज कर दिया।
- यह घटना उस समय हुई जब लड़की 2022 में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में सामूहिक बलात्कार की शिकायत दर्ज कराने थाने गई थी।

Perfect IAS

- आरोपी तिलकधारी सरोज उस समय स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) थे।
- न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार ने सरोज को तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया और उत्तर प्रदेश राज्य को आदेश दिया कि अगर उसने सहयोग नहीं किया तो उसे गिरफ्तार किया जाए।
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सरोज को न्यायिक हिरासत में भेजा जाना था.
- यह आदेश 3 मई को जारी किया गया था.

मस्तिष्क में 'हम बनाम वे' पूर्वाग्रह कहाँ से आता है? (6 मई)

- जॉर्ज ऑरवेल के पशु फार्म का उद्धरण "सभी जानवर समान हैं, लेकिन कुछ दूसरों की तुलना में अधिक समान हैं" यह दर्शाता है कि मानव समाज में पूर्वाग्रह कैसे काम करता है।
- पिछले साल मई में प्रकाशित एक अध्ययन में जांच की गई कि लोग अवचेतन रूप से विभिन्न नस्लीय समूहों का मूल्यांकन कैसे करते हैं।
- अध्ययन में 60,000 से अधिक प्रतिभागियों को शामिल किया गया था जिन्हें चार समूहों में वर्गीकृत किया गया था: 'श्वेत', 'अश्वेत', 'हिस्पैनिक' और 'एशियाई', जिनमें से अधिकांश अमेरिका में रहते थे
- अंतर्निहित एसोसिएशन टेस्ट (IAT) का उपयोग करते हुए, मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिभागियों के स्पष्ट कथनों और उनकी अंतर्निहित मान्यताओं के बीच महत्वपूर्ण अंतर पाया।
- जबकि प्रतिभागियों ने नस्लीय समानता में विश्वास व्यक्त किया, उनमें सामाजिक रूप से लाभ प्राप्त समूहों के पक्ष में अंतर्निहित पूर्वाग्रह भी थे।
- यह पूर्वाग्रह प्रतिभागियों की सभी जातीय पहचानों में सार्वभौमिक पाया गया।
- आईएटी इस सिद्धांत पर काम करता है कि यदि दो चीजें हमारे अनुभवों में बार-बार एक साथ घटित होती हैं, तो हम उन्हें तुरंत जोड़ लेते हैं।
- परीक्षण में अवधारणाओं (जैसे "पतला", "मोटा", "सफेद", "काला" आदि) और मूल्यांकन ("अच्छा" या "बुरा") से संबंधित शब्दों को श्रेणियों में छांटना शामिल है।
- प्रतिभागियों के अंक इस बात पर आधारित होते हैं कि जब अवधारणाएं और आकलन संयुक्त होते हैं तो वे कितनी शीघ्रता से शब्दों को छांटते हैं।
- उदाहरण के लिए, यदि प्रतिभागी "श्वेत" को "अच्छे" से अधिक तेजी से जोड़ते हैं, जबकि "श्वेत" को "बुरे" से जोड़ते हैं, तो इससे श्वेत लोगों के पक्ष में निहित पूर्वाग्रह का पता चलता है।

मस्तिष्क के बदलते मानदंड

- इस वैज्ञानिक तथ्य के बावजूद कि आधुनिक आनुवंशिकी के अनुसार सभी मनुष्य समान हैं, इतिहास एक ऐसी प्रवृत्ति दर्शाता है जिसमें एक सांस्कृतिक या सामाजिक समूह के लोग दूसरों को हीन समझते हैं, जिसे छद्म प्रजातिकरण के रूप में जाना जाता है।
- यह घटना मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान में गहन शोध प्रयासों का विषय बनी हुई है।
- हाल के अध्ययनों से पता चला है कि हमारा मस्तिष्क इन-ग्रुप्स ("हम") और आउट-ग्रुप्स ("उनके") के बारे में सूचनाओं को अलग-अलग तरीके से संसाधित करता है।

PatriotIAS

- फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी में 18 मार्च, 2024 को प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि हमारा मस्तिष्क दूसरों को "हम" या "वे" के रूप में वर्गीकृत करने के लिए जिन मानदंडों का उपयोग करता है, वे लगातार बदलते रहते हैं।
- अध्ययन में, आधे प्रतिभागियों से श्वेत व्यक्तियों और अश्वेत व्यक्तियों के रूप में अपने बीच अंतर का वर्णन करने के लिए कहा गया, जबकि अन्य आधे से वृद्ध व्यक्तियों और अपने बीच अंतर का वर्णन करने के लिए कहा गया।
- प्रतिभागियों का ध्यान उनकी अपनी सामाजिक पहचान के विभिन्न पहलुओं (जैसे, जाति या आयु) और बाहरी समूहों से कथित अंतरों की ओर आकर्षित करके, शोधकर्ताओं ने पाया कि इससे प्रतिभागियों के अंतर-समूह पूर्वाग्रह पर प्रभाव पड़ा।
- अध्ययन से पता चला कि प्रतिभागियों की प्राथमिकताएं इस आधार पर बदल गईं कि क्या उनके दिमाग ने दूसरों को वर्गीकृत करने के लिए उम्र या नस्ल का इस्तेमाल किया, जिससे अंतरसमूह पूर्वाग्रहों की लचीलापन पर प्रकाश डाला गया।

पूर्वाग्रह सीखा जाता है

- न्यूरोइमेजिंग अध्ययनों ने मनोविज्ञान अनुसंधान के निष्कर्षों का समर्थन किया है, जिससे पता चलता है कि मस्तिष्क में सूचना प्रसंस्करण इस पर निर्भर करता है कि यह "हम" से संबंधित है या "उनसे"।
- पूर्वकाल सिंगुलेट कॉर्टेक्स और इंसुला जैसे मस्तिष्क क्षेत्र दर्द का अनुभव करने या दूसरों के दर्द के प्रति सहानुभूति की प्रतिक्रिया में सक्रिय होते हैं।
- एक दशक पहले किए गए एक अध्ययन में इन मस्तिष्क क्षेत्रों में कम सक्रियता देखी गई थी जब व्यक्तियों ने अपने से भिन्न नस्लीय समूहों के संकटग्रस्त दूसरों की तस्वीरें देखीं।
- अन्य अध्ययनों ने भी इन निष्कर्षों की पुष्टि की है, तथा सुझाव दिया है कि नस्लीय समूहों के आधार पर विभेदकारी प्रसंस्करण से हानिरहित परिणाम, समूह के भीतर सूक्ष्म पक्षपात, या यहां तक कि संदर्भ के आधार पर अंतर-समूह हिंसा भी हो सकती है।
- पूर्वाग्रह जन्मजात नहीं होता बल्कि सीखा हुआ होता है, जो सांस्कृतिक संगति और मस्तिष्क की जीवविज्ञान से उत्पन्न होता है।
- समूह के सदस्यों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अनिवार्यतः समूह के बाहर के सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया नहीं होता।
- शत्रुता में योगदान देने वाले कारकों में बाहरी समूह को खतरे से जोड़ना शामिल है, तथा अनिश्चित परिस्थितियां, जैसे कि महामारी के दौरान, बाहरी समूह के प्रति अविश्वास को बढ़ा सकती हैं।

'जीवन के तथ्यों' के पीछे का जीवविज्ञान

- न्यूरोइमेजिंग अध्ययनों ने बादाम के आकार के मस्तिष्क क्षेत्र, एमिग्डाला की पहचान खतरों का पता लगाने और भय-आधारित सीखने के लिए केंद्रीय स्थान के रूप में की है।
- अमिगडाला समूह के बाहर के सदस्यों की धमकियों के जवाब में अधिक सक्रिय होता है, जो कथित खतरे के प्रति बढ़ी हुई प्रतिक्रिया का संकेत देता है।
- श्वेत, गैर-मुस्लिम प्रतिभागियों से जुड़े 2020 के एक अध्ययन से पता चला है कि धमकी देने वाले मुस्लिम पुरुषों के वीडियो देखने से अमिगडाला सक्रिय हो गया, जबकि सुलह के बयानों ने संज्ञानात्मक प्रसंस्करण और भावना विनियमन में शामिल विभिन्न मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय कर दिया।
- खतरों के जवाब में अमिगडाला की सक्रियता स्वचालित है, जबकि कॉर्टिकल सक्रियता संज्ञानात्मक प्रयास का सुझाव देती है।

PatriotICIAS

- तंत्रिका प्रसंस्करण और इसकी सामान्यीकरण को समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है, जो सामंजस्य के लिए रणनीतियों को सूचित कर सकता है।
- सामाजिक और सांस्कृतिक आख्यान जो कुछ समूहों को "बुरे लोगों" के रूप में चित्रित करते हैं, अक्सर मस्तिष्क जीव विज्ञान की गलत व्याख्याओं पर आधारित होते हैं।
- अपनी स्वयं की जीवविज्ञान को समझने से हमें भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने वाले आख्यानों के बारे में अधिक जानकारी और आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखने में मदद मिल सकती है।

मुल्लापेरियार बांध: विवाद का एक जलाशय

मुल्लापेरियार बांध भारत के केरल में पेरियार नदी पर बना एक गुरुत्व बांध है । आधिकारिक स्रोतों के आधार पर इसकी मुख्य विशेषताओं का विवरण इस प्रकार है:

जगह:

- इडुक्की जिला, केरल जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

निर्माण:

- जॉन पेनीकुइक द्वारा 1887 और 1895 के बीच निर्मित , तत्कालीन त्रावणकोर राज्य और ब्रिटिश जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के बीच 999 साल के पट्टा समझौते के तहत निर्मित,

विशिष्टताएं:

- चिनाई वाला गुरुत्व बांध
- ऊंचाई: नींव से 53.6 मीटर (176 फीट) लंबाई: 365.7 मीटर (1,200 फीट)
- पूर्ण जलाशय स्तर: 152 फीट
- जलाशय क्षमता: 443.23 मिलियन घन मीटर (359,332 एकड़-फीट)

कैटाटुम्बो बिजली: धारा की एक धार (6 मई)

कैटाटुम्बो बिजली, इसे एवरलास्टिंग स्टॉर्म या रिलैम्पैगो डेल कैटाटुम्बो (जिसका स्पेनिश में अर्थ है "कैटाटुम्बो की बिजली") के रूप में भी जाना जाता है, एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली वायुमंडलीय घटना है जो **कैटाटुम्बो नदी** के मुहाने पर घटित होती है। जहां यह वेनेजुएला में माराकाइबो झील में गिरती है।

WinoticIAS

कैटाटुम्बो का अनुवाद " **हाउस ऑफ थंडर** " है, जो यहां होने वाले विस्मयकारी विद्युत तमाशे को देखते हुए एक बहुत ही उपयुक्त नाम है।

कैटाटुम्बो बिजली :

- माराकाइबो झील के ऊपर और उसके आसपास होता है, आमतौर पर उस दलदल क्षेत्र पर जहां **कैटाटुम्बो नदी बहती है** झील में. तूफान की गतिविधि निर्देशांक **8°30'N 71°0'W और 9°45'N 73°0'W के बीच केंद्रित है** ।
- गवाही दीं **, जो हर दिन नौ घंटे तक चलती थीं।**
- प्रति मिनट 16 से 40 बार की चौंका देने वाली आवृत्ति पर बिजली गिरती है, जिससे यह पृथ्वी पर सबसे सक्रिय तूफान क्षेत्रों में से एक बन जाता है।
- **कैरेबियन सागर** से गर्म, नम हवा का टकराव माना जाता है कि एंडीज़ पर्वत से नीचे आने वाली ठंडी हवाएँ इस सतत तूफान का प्राथमिक कारण हैं।
- कैटाटुम्बो बिजली एक प्राकृतिक घटना है जो वेनेजुएला में कैटाटुम्बो नदी के ऊपर घटित होती है, जहाँ बिजली लगभग लगातार गिरती रहती है।
- यह मुख्य रूप से कैटाटुम्बो नदी के मुहाने पर होता है, जहां यह वेनेजुएला की सबसे बड़ी झील माराकैबो झील से मिलती है।
- कैटाटुम्बो बिजली के लिए आवश्यक अद्वितीय परिस्थितियों में कई कारक योगदान करते हैं, जिसमें कैरेबियन सागर से गर्म, नम हवा का एंडीज पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवा से टकराना शामिल है।
- यह टकराव विशाल क्यूम्यलोनिम्बस बादलों का निर्माण करता है क्योंकि गर्म हवा तेजी से ऊपर उठने के लिए मजबूर होती है।
- तेज़ हवाएँ और तापमान का अंतर इन बादलों के भीतर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, जिससे स्थैतिक बिजली का निर्माण होता है।
- जब बादलों के भीतर विद्युत क्षमता बहुत अधिक हो जाती है, तो यह बिजली के रूप में विसर्जित होती है।
- कैटाटुम्बो बिजली अपनी आवृत्ति और अवधि से भिन्न होती है, जो एक वर्ष में 160 रातों तक घटित होती है, और अपने चरम पर प्रति मिनट औसतन 28 बिजली गिरती है।
- बिजली के इस निरंतर प्रवाह के कारण, इस क्षेत्र ने "दुनिया की बिजली की राजधानी" का खिताब अर्जित किया है।

प्रधानमंत्री के भाषण आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में हैं (6 मई) (GS PAPER II: चुनाव)

यदि प्रधान मंत्री आदर्श बनना बंद कर देंगे, तो हमारे महान लोकतंत्र का कुछ भी नहीं बचेगा

आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को विनियमित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा स्थापित दिशानिर्देशों का एक सेट है। प्रचार से संबंधित व्यवहार और गतिविधियों के लिए मानक निर्धारित करके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है ।

1. **दायरा** : एमसीसी चुनाव संबंधी गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं को कवर करता है, जिसमें भाषण, अभियान, सार्वजनिक बैठकें, जुलूस और मतदान शामिल हैं।
2. **उद्देश्य** : इसका प्राथमिक उद्देश्य सभी दलों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना, चुनावी कदाचार को रोकना और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखना है।

PatrioticAS

3. **प्रवर्तन : आदर्श आचार संहिता को भारत के चुनाव आयोग द्वारा लागू किया जाता है।** चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही यह प्रभावी हो जाता है और चुनावी प्रक्रिया के समापन तक लागू रहता है।
4. **प्रमुख प्रावधान** : एमसीसी निम्नलिखित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाती है:
    - धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर मतदाताओं से अपील करना।
    - विरोधियों पर व्यक्तिगत हमले करना या अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना।
    - मतदाताओं को नकदी, शराब या अन्य प्रलोभन वितरित करना।
    - आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना पोस्टर और बैनर प्रदर्शित करना।
    - प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग करना।
5. **अनुपालन** : राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को एमसीसी के प्रावधानों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। उल्लंघन के परिणामस्वरूप **चुनाव आयोग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें फटकार, चेतावनी और यहां तक कि अयोग्यता भी शामिल है** ।
6. **महत्व** : एमसीसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने और राजनीतिक दलों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह चुनावी गतिविधियों में नैतिक आचरण और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।
7. **सार्वजनिक जागरूकता** : चुनाव आयोग मतदाताओं, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को एमसीसी के प्रावधानों और अनुपालन के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाता है।

- देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं.
- **राजनीतिक घोषणापत्र, जिसमें यह बताया जाता है कि राजनीतिक दल निर्वाचित होने पर क्या वादे करेंगे** , समाचारों में चर्चा में हैं।
- लोग इस बात पर अधिक चर्चा कर रहे हैं कि इन घोषणापत्रों में क्या छूट गया है, बजाय इसके कि इनमें क्या शामिल है।
- प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों की संपत्ति, जिसमें उनका सोना और शादी का हार (मंगलसूत्र) भी शामिल है, छीनकर अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को देना चाहती है।
- यह बयान दर्शाता है कि चुनावी बहस किस तरह चल रही है, जिसमें तथ्यों के बजाय विवादास्पद मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता होने के नाते प्रधानमंत्री और उनके सलाहकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सत्य को जानें और तथ्यों पर अडिग रहें।

दोनों घोषणापत्रों की विषय-वस्तु

- कांग्रेस पार्टी ने **' न्याय पत्र' नाम से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है.** चुनाव के लिए.
- यह देश में विभिन्न मुद्दों के बारे में बात करता है और जीतने पर पार्टी का लक्ष्य उनके बारे में क्या करना है।
- घोषणापत्र में **समानता, अल्पसंख्यक, वरिष्ठ नागरिक, विकलांगता, LGBTQIA+, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, महिला सशक्तिकरण, किसान, श्रमिक, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, कराधान और संविधान की रक्षा जैसे विषयों को शामिल किया गया है।**
- इसमें कहा गया है कि व्यवसायों के लिए धन सृजन महत्वपूर्ण है और कांग्रेस तेजी से विकास चाहती है और अगले 10 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद को दोगुना करने का लक्ष्य रखती है।
- यह इस बात पर जोर देता है कि सभी का कल्याण, विशेषकर गरीबों का कल्याण एक प्राथमिकता है और सरकारी संसाधनों का उपयोग उनके लाभ के लिए किया जाएगा।
- घोषणापत्र **में अर्थव्यवस्था में निष्पक्षता और समान अवसरों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, विशेष रूप से एससी, एसटी और ओबीसी जैसे हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए।**

PatriotiCIAS

- कांग्रेस विभिन्न जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को समझने के लिए जनगणना कराने तथा इस डेटा का उपयोग सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को मजबूत करने के लिए करने की योजना बना रही है ।
- इसमें कहीं भी एक समूह से धन लेकर दूसरे को देने का सुझाव नहीं दिया गया है। यह रॉबिन हुड की तरह पुनर्वितरण के बारे में नहीं है।
- घोषणापत्र संविधान की प्रस्तावना के सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना है जो सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करता है।

PatriotICIAS

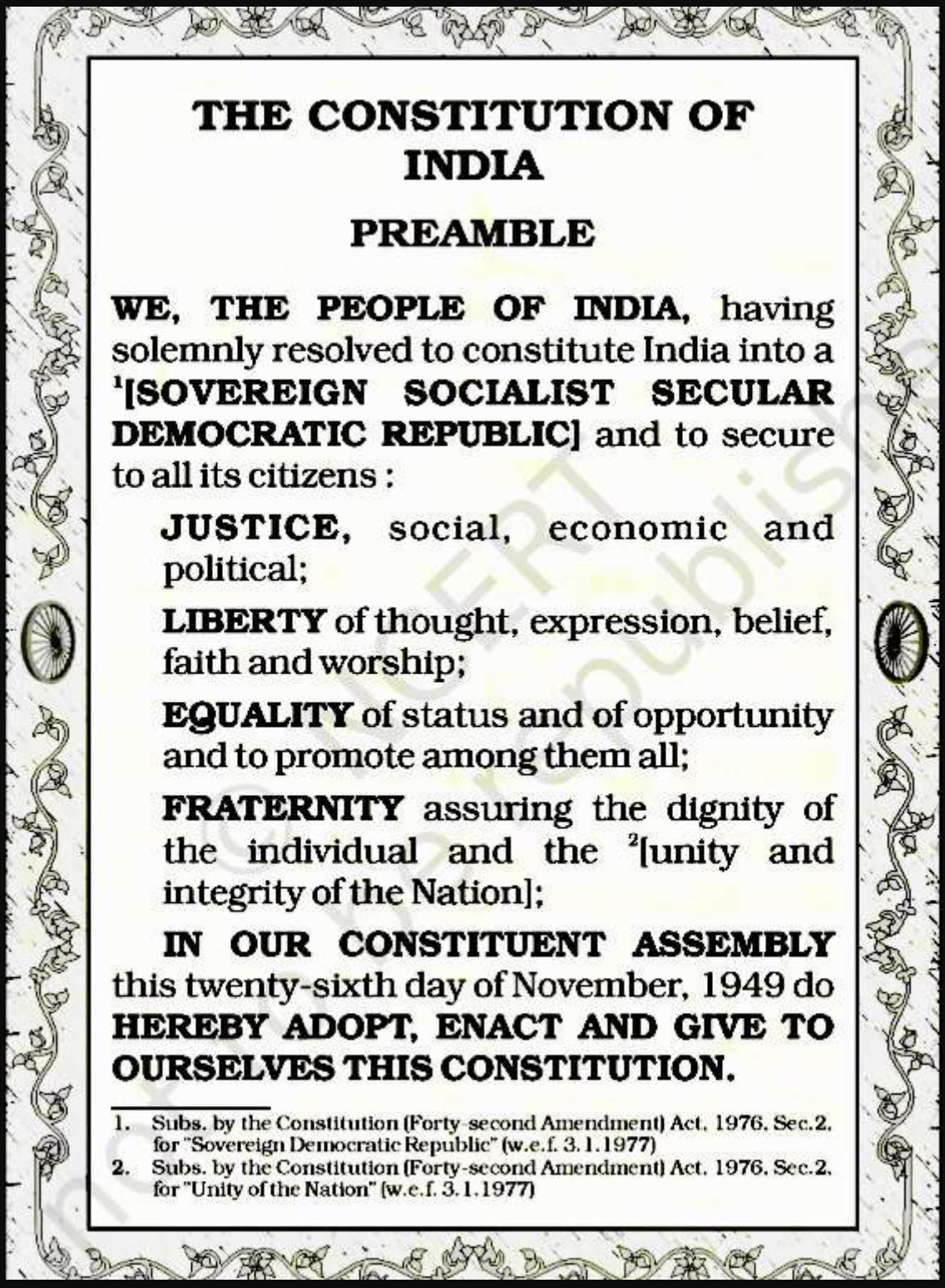

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a [1]**[SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC]** and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all;

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the [2][unity and integrity of the Nation];

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949 do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Sovereign Democratic Republic" (w.e.f. 3.1.1977)
2. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Unity of the Nation" (w.e.f. 3.1.1977)

- अनुच्छेद 39 संविधान की धारा 14 में राज्य की जिम्मेदारी बताई गई है कि वह नागरिकों के लिए पर्याप्त आजीविका सुनिश्चित करे, संसाधनों को सामान्य हित के लिए वितरित करे तथा धन के संकेन्द्रण को रोके।
- अनुच्छेद 38 इसका उद्देश्य कल्याण को बढ़ावा देने वाली सामाजिक व्यवस्था, आय असमानताओं को न्यूनतम करना, तथा स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को समाप्त करना है।

- **अनुच्छेद 46** कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- भाजपा **समान नागरिक संहिता की वकालत कर रही है,** जो नीति निर्देशक सिद्धांतों के **अनुच्छेद 44** के अनुरूप हो ।

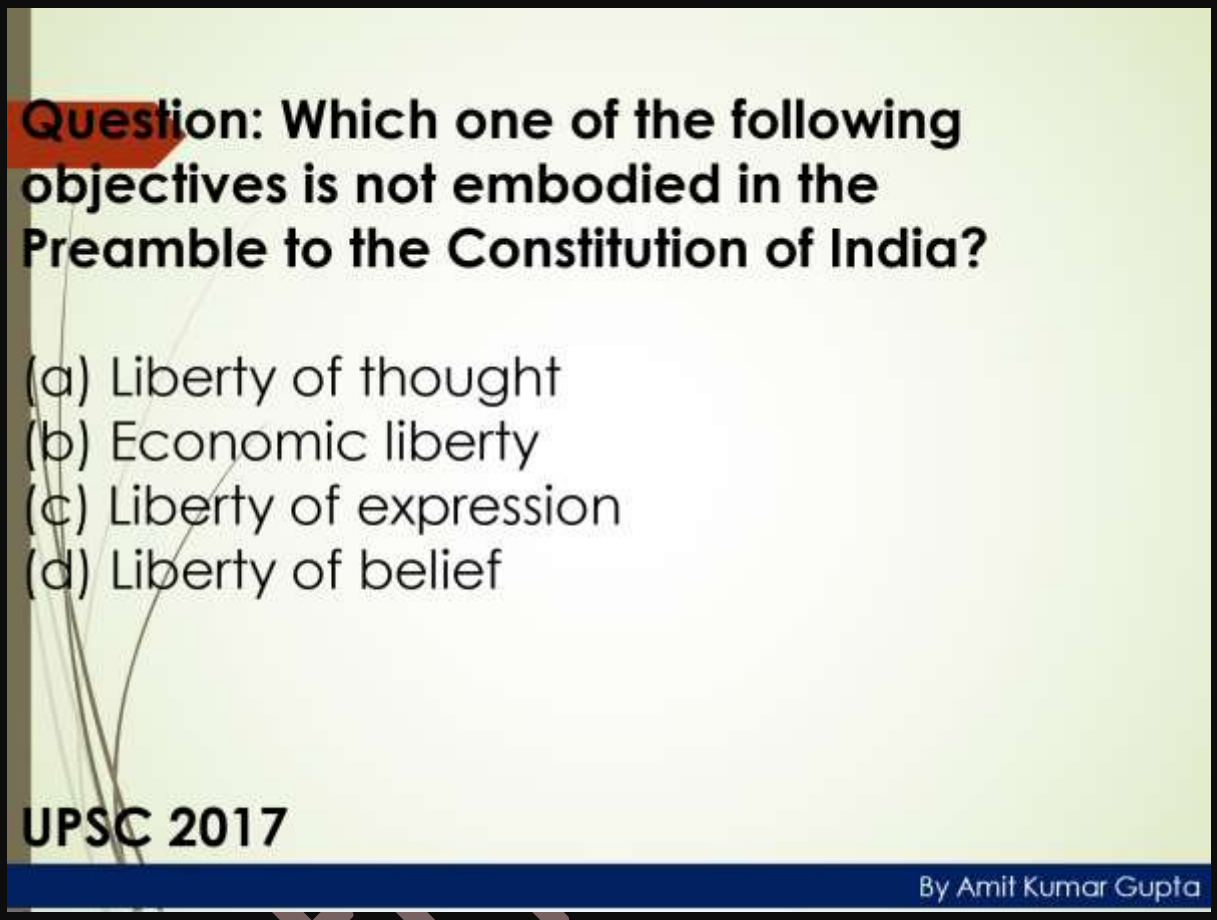

- बीजेपी **का घोषणापत्र, 'संकल्प पत्र'** मुफ्त राशन, नागरिकों के खातों में सीधे हस्तांतरण, स्वास्थ्य बीमा और आवास योजनाओं जैसी उपलब्धियों पर जोर दिया गया है।
- ये पहल संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित लक्ष्यों के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
- समान उद्देश्यों के प्रति भाजपा की अपनी प्रतिबद्धताओं को देखते हुए, कांग्रेस के घोषणापत्र के खिलाफ आरोपों को गुमराह करने वाला माना जाता है।

घोषणापत्र को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून नहीं

- में , **सुप्रीम कोर्ट (एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिल सरकार**
- **नाडु और अन्य । (2013)) ने** चुनाव घोषणापत्रों को नियंत्रित करने वाले कानूनों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- इसने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को **राजनीतिक दलों के परामर्श से दिशानिर्देश बनाने का निर्देश दिया।**
- ईसीआई ने 2013 में पार्टियों के साथ एक बैठक की और 2015 में 'घोषणापत्र पर राजनीतिक दलों को निर्देश' जारी किए।

- इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि हालांकि चुनावी वादों को भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाता है, लेकिन मुफ्त की पेशकश मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित कर सकती है।
- आदर्श **आचार संहिता (एमसीसी)** ईसीआई द्वारा 2024 में जारी किए गए आदेश उन कार्यों पर रोक लगाते हैं जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ावा दे सकते हैं या विभिन्न समूहों के बीच तनाव पैदा कर सकते हैं।
- **यह व्यक्तिगत हमलों या असत्यापित आरोपों से बचते हुए, अन्य पार्टियों की आलोचना को उनकी नीतियों और पिछले रिकॉर्ड तक सीमित रखता है।**
- एमसीसी वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील करने से भी मना करता है।
- आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों को चुनाव कानूनों के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण या अपराध माना जा सकता है।
- में , **सुप्रीम कोर्ट (डॉ. रमेश यशवंत प्रभु बनाम प्रभाकर काशीनाथ कुंटे केस, 1996) ने** बाल ठाकरे की टिप्पणियों का उदाहरण देते हुए **फैसला सुनाया कि मतदाताओं को प्रभावित करने वाले धार्मिक भाषण भ्रष्ट आचरण हैं।**
- में , **न्यायालय (अभिराम सिंह बनाम सीडी कॉमचेन केस, 2017) ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की व्याख्या करते हुए कहा कि धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर अपील भ्रष्ट आचरण है और इससे चुनाव रद्द हो सकता है।**
- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, विपक्ष और अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने वाले प्रधानमंत्री के हालिया बयान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करते हैं और भ्रष्ट आचरण का गठन करते हैं।
- लोकतंत्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री के लिए कथनी और करनी दोनों में एमसीसी का पालन करना महत्वपूर्ण है।
- **भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक रूप से अधिदेशित किया गया** है लेकिन अपने कर्तव्य में विफल रहने के लिए इसकी आलोचना की गई है, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित इसकी संरचना में खामियों का संकेत देता है।

भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय (6 मई) (GS PAPER III: आंतरिक सुरक्षा)

- एक प्राचीन यूनानी विचारक थ्यूसीडाइड्स को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है कि जो राष्ट्र अपने विद्वानों को अपने योद्धाओं से अलग करता है उसकी सोच कायरों द्वारा और उसकी लड़ाई मूर्खों द्वारा की जाएगी।
- यह उद्धरण **सैन्य संस्थानों में अकादमिक कठोरता और रणनीतिक सोच को एकीकृत करने के महत्व पर जोर देता है।**
- पाकिस्तान और चीन जैसे भारत के पड़ोसी देशों सहित कई देशों ने अपने सशस्त्र बलों में शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं।
- बताया जाता है कि पाकिस्तान में उसके सशस्त्र बलों को समर्पित दो विश्वविद्यालय हैं, जबकि चीन में तीन विश्वविद्यालय हैं, तथा चीन में 60 से अधिक अन्य विश्वविद्यालय सैन्य और सुरक्षा से जुड़े हैं।
- हालाँकि, भारत में एक समर्पित रक्षा विश्वविद्यालय का अभाव है, जबकि इसकी आवश्यकता काफी समय से है।
- **भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय (आईडीयू) की अनुपस्थिति देश की सशस्त्र सेनाओं के भीतर रणनीतिक सोच और शैक्षणिक दृढ़ता को बढ़ाने की क्षमता के बारे में चिंता पैदा करती है।**

Patriot IAS

व्यावसायिक सैन्य शिक्षा

- प्रकृति **स्थिर रहती है, लेकिन इसका चरित्र लगातार बदलता रहता है** , जिसके कारण सैन्य शिक्षा पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है।
- सैन्य अधिकारियों को वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अकादमिक तैयारी की आवश्यकता है, विशेष रूप से यूरोप और पश्चिम एशिया जैसे गतिशील और अराजक वातावरण में।
- अनिश्चित प्रारंभिक जानकारी और तेजी से बदलती परिस्थितियों के बावजूद सैन्य अधिकारियों से परिणाम देने की अपेक्षा की जाती है।
- एक अच्छी तरह से निर्मित **व्यावसायिक सैन्य शिक्षा (पीएमई)** कॉन्टिनम अधिकारियों को उनके पूरे करियर में जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए सशक्त बनाता है।
- अमेरिका में पीएमई का विकास भारत के रंगमंचीकरण के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है ।
- गोल्डवाटर -**निकोल्स रक्षा पुनर्गठन अधिनियम 1986** अमेरिका में महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार लाए गए।
- 'आइक' स्केल्टन ने अमेरिकी कांग्रेस को एक रिपोर्ट के माध्यम से अमेरिकी सशस्त्र बलों में सैन्य शिक्षा में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- स्केल्टन की रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा शैक्षिक संस्थानों को विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने, संकाय की गुणवत्ता बढ़ाने, संयुक्त अधिकारी शिक्षा के लिए दो-चरणीय प्रणाली स्थापित करने और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान बनाने की सिफारिश की गई थी।

धीमी प्रगति

- **रक्षा सेवा विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार पहली बार 1967 में चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी द्वारा प्रस्तावित किया गया था।**
- **1982 में,** एक अध्ययन समूह ने सशस्त्र बलों के लिए एक सर्वोच्च शैक्षणिक निकाय की आवश्यकता पर बल दिया, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय (आईडीयू) की अवधारणा सामने आई ।
- **कारगिल संघर्ष के बाद, आईडीयू की स्थापना की जांच के लिए डॉ. के. सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी।**
- समिति की सिफारिशों के आधार पर मई 2010 में **गुड़गांव में आईडीयू की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी गई।**
- प्रारंभिक आशावाद के बावजूद, आईडीयू की स्थापना की प्रगति धीमी रही है।
- **भारत के सशस्त्र बलों के पास कई विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और शिक्षा संस्थान हैं, लेकिन उनमें पर्याप्त कौशल की कमी है।** एक एकीकृत व्यावसायिक सैन्य शिक्षा (पीएमई) ढांचा।
- डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों से संबद्धता को सशस्त्र बलों की शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए इष्टतम समाधान के रूप में नहीं देखा जाता है।
- आईडीयू **का उद्देश्य शिक्षाविदों और सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों से युक्त योग्य संकाय के साथ उच्च सैन्य शिक्षा का एक केंद्रीय संस्थान प्रदान करके इन कमियों को दूर करना है।**
- विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम **राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों को कवर करेगा, जिसमें सिद्धांत को व्यवहार के साथ एकीकृत किया जाएगा।**
- आईडीयू के प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न कॉलेज और संस्थान रक्षा और सुरक्षा से संबंधित विज्ञान और मानविकी में विविध विषयों की पेशकश करेंगे।

एक ख़्याल जिसका समय आ गया है

PatriotIAS

- रक्षा विश्वविद्यालय (आईडीयू) की स्थापना लंबे समय से लंबित होने के बावजूद इसमें देरी हो रही है।
- कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि **गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू)** IDU की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। हालाँकि, यह तर्क त्रुटिपूर्ण है।

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) राष्ट्रीय सुरक्षा, पुलिस अध्ययन और अपराध प्रबंधन के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए समर्पित एक प्रमुख संस्थान है। आधिकारिक स्रोतों के आधार पर इसकी प्रमुख विशेषताओं का विवरण इस प्रकार है:

स्थापना:

- राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 के माध्यम से 2020 में स्थापित

जगह:

- गांधीनगर, गुजरात, भारत

दृष्टि और लक्ष्य:

- **विज़न:** राष्ट्रीय सुरक्षा, पुलिस अध्ययन और अपराध प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए एक विश्व स्तरीय केंद्र बनना ।
- **मिशन:** राष्ट्रीय सुरक्षा, पुलिस और संबद्ध क्षेत्रों के लिए अत्यधिक कुशल और पेशेवर मानव संसाधन विकसित करने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना।

शैक्षणिक:

- निम्नलिखित से संबंधित विभिन्न विशेषज्ञताओं में स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट और डिप्लोमा कार्यक्रम प्रदान करता है:
    - पुलिस प्रशासन
    - अपराध विज्ञान और आपराधिक न्याय
    - साइबर सुरक्षा
    - फोरेंसिक विज्ञान
    - आंतरिक सुरक्षा
    - आपदा प्रबंधन
    - कानूनी अध्ययन (सुरक्षा कानून पर ध्यान केंद्रित)

महत्व:

- भारत में प्रथम विश्वविद्यालय जो पूर्णतः पुलिस और सुरक्षा अध्ययन के लिए समर्पित है।
- समकालीन सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अंतःविषयक शिक्षण और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करता है।
- इसका उद्देश्य व्यावहारिक प्रशिक्षण और वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों से परिचय कराकर सिद्धांत और व्यवहार के बीच की खाई को पाटना है।

- आईडीयू और आरआरयू के बीच तुलना सेब और संतरे की तुलना करने जैसी है, क्योंकि उनके उद्देश्य और पाठ्यक्रम काफी भिन्न हैं।
- आरआरयू अधिनियम अपने उद्देश्यों में '**रक्षा' से संबंधित शिक्षा को निर्दिष्ट नहीं करता है, और इसका पाठ्यक्रम केवल युद्ध प्रबंधन और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सैन्य आवश्यकताओं पर केंद्रित नहीं है।**
- आईडीयू के चालू होने में देरी से रक्षा तैयारी, रणनीतिक संस्कृति और अंतर-सेवा एकीकरण पर असर पड़ता है।
- एक सुव्यवस्थित और भविष्योन्मुखी सैन्य शिक्षा पाठ्यक्रम के माध्यम से संयुक्त युद्ध के लिए आधार तैयार करने हेतु IDU को शीघ्र क्रियान्वित करने की तत्काल आवश्यकता है।

PatrioticIAS

अग्रिम पंक्ति में: राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर (6 मई)

राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था

- राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जो उनके परिवार के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र है।
- उनकी दादी, दादा और मां सभी ने अतीत में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया है।
- 2019 में, राहुल गांधी अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से हार गए, लेकिन केरल के वायनाड से जीत गए।
- उन्होंने वायनाड से पुनः चुनाव लड़ते हुए रायबरेली से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है।
- रायबरेली से चुनाव लड़ने का उनका फैसला नामांकन की समय सीमा से ठीक पहले आया, जिससे उनके इरादों के बारे में अटकलें लगने लगीं।
- उनकी बहन, प्रियंका गांधी वाद्रा ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया, जबकि उनके पति, रॉबर्ट वाद्रा, जिन्होंने पार्टी टिकट में रुचि व्यक्त की थी, को नजरअंदाज कर दिया गया।
- राहुल गांधी ने भाजपा की हिंदुत्व राजनीति का विरोध करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने, विशेष रूप से हिंदी बेल्ट और पश्चिमी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने मिशन की घोषणा की है।
- इन क्षेत्रों में भाजपा का गढ़ है, जबकि कांग्रेस अपना प्रभाव वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही है।
- उत्तर प्रदेश में कड़ी लड़ाई से बचने के लिए 2019 में केरल से चुनाव लड़ने के राहुल गांधी के फैसले को एक रणनीतिक गलती के रूप में देखा गया।
- उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उनके उतरने से विपक्ष में जोश आ सकता है, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन से।
- वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों पर जीत के लिए राहुल गांधी को रायबरेली सीट बरकरार रखनी होगी, जो दीर्घावधि में भाजपा के खिलाफ वैचारिक लड़ाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का संकेत होगा ।

बदलाव की चाहत: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में चुनाव (6 मई)

कश्मीर और लद्दाख में विपक्ष चुनावी नहीं, बल्कि अपने उद्देश्यों को लेकर एकजुट है

- जम्मू और कश्मीर, लद्दाख सहित, पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य से निर्मित केंद्र शासित प्रदेश हैं।
- इन क्षेत्रों में कई चरणों में चुनाव हो रहे हैं।
- जम्मू निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान पहले ही हो चुका है और मतदान प्रतिशत उत्साहजनक रहा है।
- हालाँकि, श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला जैसे कश्मीर घाटी के निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कम रहा।
- इस कम मतदान का कारण राज्य विधानसभा के विघटन और केंद्रीय शासन जारी रहने के कारण मतदाताओं में मोहभंग है।

PatriotIAS

- जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा और केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा ख़त्म करने से कश्मीरियों में अलगाव की भावना और गहरी हो गई है।
- कश्मीरी पार्टियों और नई दिल्ली के बीच अविश्वास के बावजूद, पीडीपी और एनसी जैसी पारंपरिक पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ने के लिए एकजुट नहीं हुई हैं।
- जम्मू और लद्दाख पर भाजपा के फोकस के साथ-साथ देश को "एकीकृत" करने की बात को खोखला बताकर आलोचना की गई है।
- लद्दाख में, कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अभियान ने राज्य के दर्जे और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के मुद्दों पर प्रकाश डाला है।
- हालाँकि, कांग्रेस और एनसी जैसी विपक्षी पार्टियाँ लद्दाख निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक आम सहमति वाले उम्मीदवार पर सहमत नहीं हो सकीं, जिसके परिणामस्वरूप उनका समर्थन विभाजित हो गया।

अमीरों को गरीब बनाये बिना गरीबों को अमीर बनाओ (6 मई)

यह निर्विवाद है कि पिछले दो दशकों में अमीर और गरीब के बीच आर्थिक असमानता चिंताजनक रूप से बढ़ी है, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में।

पैरेटो इष्टतमता, या पैरेटो दक्षता , अर्थशास्त्र में एक अवधारणा है जो एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जहां **किसी अन्य व्यक्ति की स्थिति को बदतर बनाये बिना किसी व्यक्ति की स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता है** ।
यह एक ऐसी स्थिति है जहां सभी व्यक्तियों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का आवंटन यथासंभव सबसे कुशल तरीके से किया जाता है।

- पेरेटो **सीमांत दर्शाता है** दो उद्देश्यों के विभिन्न संयोजन जिन्हें किसी को भी नुकसान पहुंचाए बिना प्राप्त किया जा सकता है।
- वक्र पर किसी भी बिंदु को **पेरेटो इष्टतम माना जाता है** , जबकि वक्र के नीचे के बिंदुओं को अक्षम माना जाता है।

पेरेटो इष्टतमता:

- यह एक सैद्धांतिक अवधारणा है, और व्यवहार में, वास्तव में पेरेटो इष्टतम परिणाम प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है।
- पेरेटो इष्टतमता का **अर्थ समानता या निष्पक्षता नहीं है** । यह संसाधनों के सबसे कुशल आवंटन की पहचान करने का एक तरीका है।
- पेरेटो इष्टतमता की अवधारणा का उपयोग अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और इंजीनियरिंग सहित कई अलग-अलग क्षेत्रों में किया जाता है।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर अपने घोषणापत्र में धन पुनर्वितरण का वादा करने का आरोप लगाया है, लेकिन दस्तावेज़ में इसका कोई उल्लेख नहीं है।
- इससे भारत और विश्व स्तर पर असमानता पर बहस छिड़ गई, पिछले दो दशकों में आर्थिक असमानता काफी बढ़ गई है।
- इस मुद्दे का राजनीतिकरण धन के अंतर को पाटने के लिए वास्तविक समाधान खोजने से रोकता है।
- इस अंतर को पाटने का काम अमीरों को और गरीब बनाकर, गरीबों को और अमीर बनाकर या दोनों से किया जा सकता है।

PatriotIAS

- **पेरेटो ऑप्टिमम"** की अवधारणा सुझाती है एक व्यक्ति की स्थिति में सुधार से दूसरे की स्थिति खराब हो सकती है, जो धीमी वृद्धि वाले विकसित देशों में प्रासंगिक है।
- हालाँकि, तेज़ विकास दर वाले विकासशील देशों के पास असमानता को दूर करने के लिए अधिक विकल्प हैं, जो वैचारिक दृष्टिकोण में एक बुनियादी अंतर प्रस्तुत करता है।

'सिस्टम ठीक करें'

- का विचार , **जिसका उद्देश्य गरीबों की सहायता के लिए अति-धनवानों से धन निकालना है, आर्थिक असमानता को कम करने के लिए 'शून्य-योग' दृष्टिकोण पर आधारित है** ।
- अनुचित साधनों से अर्जित धन पर कर लगाने से प्रक्रिया और परिणाम एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिससे धन पर सीधे निशाना साधने के बजाय व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता का सुझाव मिलता है।
- उत्तराधिकार कर, नैतिक रूप से आकर्षक होते हुए भी, आर्थिक असमानता पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डाल सकता है तथा निवेश को बाधित कर सकता है।
- भारत की आर्थिक वृद्धि समग्र आर्थिक विस्तार के लिए आवश्यक है, जिसके लिए निवेश की आवश्यकता है, जिसमें आक्रामक कराधान नीतियां बाधा उत्पन्न कर सकती हैं।
- भारत की असमानता विषम आर्थिक वृद्धि और कराधान से उत्पन्न होती है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है, जहां सकल घरेलू उत्पाद का विस्तार बहुसंख्यकों के लिए रोजगार और समृद्धि में परिवर्तित नहीं होता।
- श्रम -केंद्रित नीति प्रोत्साहनों के माध्यम से पूंजी- श्रम विषमता को पुनर्संतुलित करने की आवश्यकता है , जैसा कि कांग्रेस के घोषणापत्र में कुछ वादों में देखा गया है, जैसे युवाओं के लिए प्रशिक्षुता का अधिकार और कॉर्पोरेट्स के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं।
- कराधान में असंतुलन के कारण भारत की असमानता बढ़ गई है, जहां आम व्यक्ति कॉरपोरेट्स की तुलना में अधिक कर चुकाता है।
- करों में एकत्रित प्रत्येक 100 रुपये में से 64 रुपये गरीब और मध्यम वर्ग से अप्रत्यक्ष (जीएसटी) और आयकर के माध्यम से आते हैं, जबकि केवल 36 रुपये अमीर कॉरपोरेट्स से आते हैं।
- इससे गरीबों और आम लोगों को आर्थिक विकास के लाभों से बाहर होने और कॉरपोरेट्स की तुलना में अधिक कर लगाने का दोहरा बोझ झेलना पड़ता है।
- घोषणापत्र का उद्देश्य भारत के कराधान ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन का प्रस्ताव करना है, जिसमें सरल और निम्न जीएसटी दरें तथा एक नया प्रत्यक्ष कर कोड शामिल है।
- कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा जाल गरीबों को तब तक सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है, जब तक कि वे आर्थिक विकास से लाभान्वित न हो जाएं।
- कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए वित्तपोषण तीव्र विकास, उच्च कर-क्षमता तथा अमीरों को दंडित किए बिना कुशल कल्याणकारी वितरण से आ सकता है।
- अमीर-गरीब के बीच के अंतर को कम करने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण में आर्थिक विकास को अधिकतम करना, बेरोजगारी को न्यूनतम करना, आम आदमी के लिए कर का बोझ कम करना और गरीबों को सुरक्षा प्रदान करना शामिल है।
- श्रम बाजार प्रोत्साहन, कल्याण सुरक्षा जाल और निवेश आकर्षित करने के बीच एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता है ।
- गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए अमीरों पर दंडात्मक कर लगाना व्यावहारिक, बुद्धिमानी भरा या वांछनीय नहीं माना जाता है। इसके बजाय, भारत गरीबों को और अधिक अमीर बनाने पर ध्यान केंद्रित करके असमानता को कम कर सकता है, बिना अमीरों को और अधिक गरीब बनाए।

PathOfIAS

प्रश्न 1: निम्नलिखित में से कौन सा तालवाद्य नहीं है? (क) ढोल (ख) सितार (सी) ज़ाइलोफोन (घ) ढोलकी	उत्तर: (बी) सितार **व्याख्या:** ताल वाद्य यंत्रों को जब मारा या पीटा जाता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। सितार एक तार वाला वाद्य यंत्र है जिसे तारों को झंकृत करके बजाया जाता है। ढोल , ज़ाइलोफोन और ढोलकी सभी ताल वाद्य यंत्र हैं।
तबले पर बजाए जाने वाले भारतीय शास्त्रीय संगीत में लयबद्ध पैटर्न को कहा जाता है: (ए) ताल (बी) राग (सी) सरगम (डी) भटियाली	उत्तर: (ए) ताल **स्पष्टीकरण:** ताल भारतीय शास्त्रीय संगीत में लयबद्ध चक्र को संदर्भित करता है, जिसे अक्सर तबले पर बजाया जाता है । राग मधुर ढांचे को परिभाषित करता है, सरगम संगीत का पैमाना है, और भटियाली बंगाल में लोक संगीत की एक विशिष्ट शैली है।
प्रश्न 3: भारत के निम्नलिखित में से किस आदिवासी नृत्य में ढोल प्रमुखता से बजाया जाता है? (ए) भांगड़ा (बी) बिहू (सी) गरबा (घ) घूमर	उत्तर: (ए) भांगड़ा **व्याख्या** : ढोल एक दो सिर वाला बैरल ड्रम है, जो पंजाब के ऊर्जावान भांगड़ा नृत्य में एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। बिहू (असम), गरबा (गुजरात), और घूमर (राजस्थान) के अपने अलग ताल वाद्य हैं।
प्रश्न 4: कैटाटुम्बो बिजली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: (i) यह एक अनोखी प्रकार की बिजली है जो वेनेजुएला में कैटाटुम्बो नदी पर गिरती है। (ii) यह पृथ्वी पर दर्ज की गई सबसे अधिक बार होने वाली बिजली गिरने की गतिविधि है। (iii) इस घटना का कारण पूरी तरह से समझा नहीं गया है। (iv) यह वेनेजुएला का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? (a) केवल (i) और (ii) (बी) केवल (i), (ii) और (iii) (c) केवल (i), (iii) और (iv) (D। उपरोक्त सभी	उत्तर: (डी) उपरोक्त सभी **स्पष्टीकरण:** कैटाटुम्बो बिजली एक सुप्रलेखित घटना है जो वेनेजुएला में कैटाटुम्बो नदी पर घटित होती है। यह अपनी असाधारण आवृत्ति के लिए जाना जाता है, अनुमान है कि चरम गतिविधि के दौरान प्रति मिनट 40 बिजली गिरती है। यह इसे पृथ्वी पर सबसे अधिक बार होने वाली बिजली गतिविधि के खिताब का एक मजबूत दावेदार बनाता है। इस अत्यधिक बिजली की सघनता के सटीक कारण पर अभी भी शोध किया जा रहा है, लेकिन विशिष्ट वायुमंडलीय स्थितियों और आस-पास के दलदल से मीथेन गैस की उपस्थिति जैसे कारकों को एक भूमिका निभाने के लिए माना जाता है। अपने शानदार लाइट शो के कारण, कैटाटुम्बो लाइटनिंग वास्तव में वेनेजुएला में एक पर्यटक आकर्षण है, जिसे अक्सर "द एवरलास्टिंग स्टॉर्म" कहा जाता है।

PatriotIAS

प्रश्न 5: कैटाटुम्बो बिजली की घटना संभवतः निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? (ए) ज्वालामुखीय गतिविधि (बी) अद्वितीय वायुमंडलीय स्थितियाँ (सी) बड़े जल निकायों की उपस्थिति (डी) टेक्टोनिक प्लेटों की गति	उत्तर: (बी) अद्वितीय वायुमंडलीय परिस्थितियाँ **स्पष्टीकरण** : ज्वालामुखीय गतिविधि, टेक्टोनिक प्लेटों की गति और बड़े जल निकाय सीधे तौर पर कैटाटुम्बो बिजली से जुड़े नहीं हैं। जबकि जल वाष्प बिजली निर्माण में भूमिका निभाता है, कैटाटुम्बो क्षेत्र में विशिष्ट वायुमंडलीय स्थितियां, संभवतः मीथेन उत्सर्जन से प्रभावित होती हैं, इस घटना के लिए प्रमुख चालक मानी जाती हैं।
प्रश्न 6: मुल्लापेरियार बांध किन दो भारतीय राज्यों के बीच विवाद का विषय है? (ए) केरल और कर्नाटक (बी) केरल और आंध्र प्रदेश (सी) केरल और तमिलनाडु (डी) तमिलनाडु और कर्नाटक	उत्तर: (सी) केरल और तमिलनाडु **स्पष्टीकरण** : मुल्लापेरियार बांध केरल में स्थित है, लेकिन यह तमिलनाडु के कुछ हिस्सों की सिंचाई के लिए पानी की दिशा बदलता है। बांध की सुरक्षा को लेकर चिंताओं के कारण दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है ।
मुल्लापेरियार बांध से जुड़ी प्रमुख चिंता क्या है ? (ए) उच्च रखरखाव लागत (बी) अकुशल जल उपयोग (ग) भूकंपीय भेद्यता (घ) जलाशय में गाद जमना	उत्तर: (सी) भूकंपीय भेद्यता **स्पष्टीकरण** : बांध की उम्र और भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसकी भूकंप को झेलने की क्षमता पर चिंता जताई गई है। यह केरल और तमिलनाडु के बीच विवाद का एक प्रमुख मुद्दा है।
प्रश्न 8: मुल्लापेरियार बांध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? (ए) इसका निर्माण ब्रिटिश राज के दौरान किया गया था। (बी) यह पेरियार नदी पर स्थित है। (सी) बांध महत्वपूर्ण मात्रा में पनबिजली उत्पन्न करता है। (डी) भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बांध के संचालन के संबंध में फैसले जारी किए हैं।	उत्तर: (सी) बांध महत्वपूर्ण मात्रा में पनबिजली उत्पन्न करता है। **स्पष्टीकरण** : हालाँकि बाँध कुछ जलविद्युत उत्पन्न करता है, सिंचाई इसका प्राथमिक उद्देश्य बना हुआ है। सिंचाई पर ध्यान बांध के डिजाइन और क्षमता में परिलक्षित होता है।
प्रश्न 10: राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उद्देश्य है : (ए) कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। (बी) कानून प्रवर्तन और सुरक्षा में शामिल कर्मियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्रदान करें। (सी) इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में उन्नत डिग्री प्रदान करें। (डी) भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर ध्यान दें	उत्तर: (बी) कानून प्रवर्तन और सुरक्षा में शामिल कर्मियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्रदान करें। **स्पष्टीकरण** : आरआरयू का ध्यान पुलिसिंग, आपराधिक न्याय और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण और शिक्षा पर है। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की आवश्यकता को पूरा करना है। अन्य विकल्प विश्वविद्यालय के मूल उद्देश्य से मेल नहीं खाते।

PatriotIAS

प्रश्न 11: गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) का स्थान अन्य संस्थानों की उपस्थिति के कारण लाभप्रद हो सकता है: (ए) मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। (बी) प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग संस्थान। (सी) राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय। (डी) कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र ।	उत्तर: (सी) राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय। स्पष्टीकरण: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की उपस्थिति कानून प्रवर्तन, आपराधिक न्याय और साक्ष्य संग्रह से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग और अंतःविषय सीखने का अवसर पैदा करती है। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, प्रौद्योगिकी संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र सीधे तौर पर आरआरयू के मुख्य फोकस से संबंधित नहीं हैं।

PatrioticIAS